यू. पी. सुन्नी वक्फ का केंद्रीय बोर्ड

वी.

मज़हर हसन और ओआरएस,

9 अगस्त, 2001

[एस. राजेंद्र बाबू और डी. पी. मोहपात्र, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960:धारा 29 (8) और 33

वक्फ-अस्तित्व में आना-मुसलमान जनता द्वारा दिए गए दान से निर्मित कुछ संपत्तियां-दान का उद्देश्य धर्मार्थ और धार्मिक था-वक्फ के रूप में पंजीकृत ऐसी संपत्तियां-उच्च न्यायालय ने पंजीकरण को दरकिनार कर दिया-की शुद्धता-आयोजितःयदि सामान्य सार्वजनिक द्वारा दिए गए दान से धर्मार्थ, पवित्र या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति खरीदी जाती है, तो ऐसी संपत्ति 'वक्फ' का चरित्र नहीं खोती है-इसलिए, ऐसी संपत्ति एक स्थायी चरित्र प्राप्त करती है-इसलिए, उच्च न्यायालय पंजीकरण को रद्द करने में उचित नहीं है।

शब्द और वाक्यांशः

“वक्फ का अर्थ-यू. पी. मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के संदर्भ में।

प्रतिवादी ने यू. पी. मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 29 (8) और 33 के तहत मुक़दमा संपत्ति के वक्फ़ के रूप में पंजीकरण को रद्द करने के मुकदमा एक संदर्भ दिया।अपीलकर्ता द्वारा इस संदर्भ का इस आधार पर विरोध किया गया कि विचाराधीन भूमि मुसलमान जनता द्वारा दी गई सदस्यता से खरीदी गई थी और इमारत का निर्माण भी आम जनता द्वारा दिए गए ऐसे दान से किया गया था; कि इस निधि के संग्रह या आम तौर पर मुसलमानों द्वारा किए गए दान का उद्देश्य एक धर्मार्थ था, जिसका नाम मुस्लिम मुसाफिरखाना का निर्माण था; कि उन्हें आवास की

कमी से राहत देने और धार्मिक उद्देश्य के लिए मुसाफिरखाना के भीतर एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया था; और इसलिए, पंजीआदेशण कानून के अनुसार था। न्यायाधिकरण ने संदर्भ की अनुमति दी और पंजीकरण को दरकिनार कर दिया, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की।इसलिए यह अपील की गई है।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए,अभिनिर्धारित किया।

1. यदि किसी संपत्ति को एक निश्चित उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है, तो ऐसी संपत्ति एक उद्देश्य के लिए 'समर्पित' हो जाएगी।यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल उन मामलों में है जब कोई व्यक्ति उचित रूप से खुद को अलग करता है और विश्वास की घोषणा के बाद यह बसने वाले पर उस उद्देश्य के लिए बाध्यकारी है जिसके लिए बाद में संपत्ति रखी जानी है।यदि आम जनता द्वारा दिए गए धन में से कोई संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए खरीदी जाती है, जो धार्मिक या धर्मार्थ चरित्र की है, तो ऐसी संपत्ति यू. पी. मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के तहत परिभाषित 'वक्फ' के रूप को नहीं खोएगी।जिस उद्देश्य के लिए विचाराधीन संपत्ति को अलग किया गया है या समर्पित किया गया है, वह धर्मार्थ, पवित्र या धार्मिक प्रकृति का है और इसलिए समर्पण पूर्ण था और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता था।इसलिए, जब संपत्ति का उपयोग केवल धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, तो यह एक स्थायी चरित्र प्राप्त करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित आदेशने में न्यायोचित नहीं है कि न्यायाधिआदेशण द्वारा पंजीआदेशण को रद्द आदेशना क्रम में है।[382-सी, डी, ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः1995 दीवानी याचिका सं 11988

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश मे पारित 1978 के सी. आर., सं. 595 में 11.04.94 दिनांकित से

अपीलकर्ता की ओर से शकील अहमद सैयद।

उत्तरदाताओं के लिए इरशाद अहमद।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश राजेंद्र बाबू, द्वाराजे. सुनाया गया।

वक्फ के रूप में कुछ संपत्तियों के पंजीकरण पर उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की खंड 29 (8) और खंड 33 [इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित] के तहत प्रतिवादी द्वारा पंजीकरण रद्द करने के लिए एक संदर्भ दिया गया था।विचाराधीन संपत्ति को बहराइच शहर के काजीपुरा में स्थित एक मुस्लिम मुसाफिरखाना बताया गया है, जिसमें 24 कमरे, एक कोर्ट-यार्ड, वरांडा, खुली जमीन, मार्ग, चार दुकानें, कार्यालय कक्ष और कुछ निर्माणाधीन हिस्सा है जो शिकायत में इंगित किया गया है और उस आवास के भीतर एक मस्जिद मौजूद है लेकिन जिसे शिकायत में शामिल नहीं किया गया था।प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला यह है कि विचाराधीन संपत्ति एक सोसायटी के स्वामित्व में थी, जिसके प्रतिमुकदमा पदाधिकारी रहे हैं; कि वे मुकदमा संपत्ति के कब्जे में रहे हैं; कि उन्होंने 18 अक्टूबर, 1966 को उक्त भूमि खरीदी, जिस पर आवास मौजूद है। दो महिलाओं से 6,100 और उसके बाद उस भूमि पर मुसाफिरखाना का निर्माण कराया गया; कि अधिनियम की धारा 29 से 33 के प्रावधान लागू नहीं हुए और इसलिए विमुकदमाग्रस्त संपत्ति का वक्फ के रूप में पंजीकरण अवैध, अमान्य था।अपीलकर्ता द्वारा इस संदर्भ का इस आधार पर विरोध किया गया कि विचाराधीन भूमि मुसलमान जनता द्वारा दी गई सदस्यता से खरीदी गई थी और इमारत का निर्माण भी आम जनता द्वारा दिए गए ऐसे दान से किया गया था; कि इस निधि के संग्रह या आम तौर पर मुसलमानों द्वारा किए गए दान का उद्देश्य धर्मार्थ था, अर्थात्, मुस्लिम मुसाफिरखाने का निर्माण; कि उन्हें आवास की कमी से राहत देने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसाफिरखाने के भीतर

एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया था; कि, इसलिए, पंजीआदेशण कानून के अनुसार था।

न्यायाधिकरण ने माना कि मस्जिद मुसाफिरखाना का अभिन्न अंग है और इसका एक धार्मिक उद्देश्य है और मुसाफिरखाना धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए है और मुसाफिरखाना के अभिन्न अंग के रूप में एक मस्जिद के अस्तित्व के कारण यह एक धार्मिक चरित्र भी है।हालांकि, इस आधार पर कि कथित वक्फ संपत्ति मुसलमान धर्म का दावा करने वाले द्वारा स्थायी रूप से समर्पित की गई थी और समर्पण के उद्देश्यों को धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ साबित किया जाना चाहिए, यह केवल ऐसे मामले में कहा जा सकता है कि वक्फ अस्तित्व में आया था और मुस्लिम धर्म रखने वाले समर्पित व्यक्ति द्वारा समर्पण के प्रमाण की अनुपस्थिति में में विवादित संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं कहा जा सकता था और इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता था, न्यायाधिकरण ने संदर्भ की अनुमति दी और पंजीकरण को रद्द कर दिया।इस मामले को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में ले जाया गया, जिसने न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।इसलिए विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज कियाः-

> "वर्तमान मामले में, मुस्लिम जनता के लिए मुसाफिरखाने का निर्माण या निर्माण को किसी भी संदेह से परे परोपकारी, पवित्र और धर्मार्थ उद्देश्य कहा जा सकता है जैसा कि नीचे दी गई अदालत ने पाया है। यह धार्मिक भी हो सकता है, यानी, जिस उद्देश्य के लिए लोगों से सदस्यता की मांग की गई थी।सदस्यता का उद्देश्य या उद्देश्य, यानी मुसाफिरखाना का निर्माण, इसमें कोई संदेह नहीं है, पवित्र, धर्मार्थ और धार्मिक है, लेकिन अन्य तत्व, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया

है, यह है कि स्वैच्छिक समर्पण और समर्पण मुसलमान धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, जैसा कि नीचे दी गई अदालत द्वारा पाया गया रिकॉर्ड साक्ष्य भी इंगित करता है कि सदस्यता की मांग करने वाली अपील जारी किए जाने के बाद बहराइच के लोगों से सदस्यता के लिए एक बैठक बुलाई गई थी और धन आया था।एक्स. ए. एल. 2-ऑन रिकॉर्ड वह अपील है जो दान की मांग करते हुए जारी की गई थी और उसके अनुसरण में पी. डब्ल्यू. 1 निजामुद्दीन और अन्य गवाहों के बयान के अनुसार बहराइच की जनता से धन आया था जिन्होंने सदस्यता या दान की पेशकश की थी।इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से दान किया था।"

उच्च न्यायालय का विचार है कि समर्पण अपने साथ बिना किसी मांग या अपील के स्वैच्छिक स्व-दान का विचार रखता है और बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा की जा रही अपील पर की गई सदस्यता या दान को स्थायी चरित्र की संपत्ति का दान नहीं माना जा सकता है जो अधिनियम के तहत 'वक्फ' की परिभाषा का आवश्यक घटक है। यदि किसी संपत्ति को एक निश्चित उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है, तो ऐसी संपत्ति एक उद्देश्य के लिए 'समर्पित' हो जाएगी।यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल उन मामलों में है जब कोई व्यक्ति संपत्ति से खुद को अलग करता है और विश्वास की घोषणा के बाद यह बसने वाले पर उस उद्देश्य के साथ बाध्यकारी है जिसके लिए संपत्ति को उसके बाद रखा जाना है।यदि आम जनता द्वारा दिए गए धन में से कोई संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए खरीदी जाती है जो धार्मिक या धर्मार्थ है, तो हमें नहीं लगता कि ऐसी संपत्ति अधिनियम के तहत परिभाषित 'वक्फ' के रूप को खो देगी। उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष, न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, स्वयं इंगित करता है कि जिस उद्देश्य के लिए विचाराधीन संपत्ति

को अलग किया गया है या समर्पित किया गया है, वह धर्मार्थ, पवित्र या धार्मिक प्रकृति का है और इसलिए, समर्पण पूर्ण था और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता था।इसलिए, जब संपत्ति का उपयोग केवल धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, तो यह एक स्थायी चरित्र प्राप्त करता है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम नहीं सोचते हैं कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित आदेशने में उचित है कि न्यायाधिआदेशण द्वारा पंजीआदेशण को रद्द आदेशना क्रम में है।न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी द्वारा दिए गए संदर्भ को खारिज कर दिया जाता है।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।